

समस्या कणवघाटी

RNI No.: UTTHIN/2013/54659

वर्ष-12

अंक-23

हरिद्वार, गुरुवार, 15 अक्टूबर, 2025

मूल्य-दो रूपया मात्र

पृष्ठ-8

राज्य में सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया जायेगा : मुख्यमंत्री

गुप्तकाशी में चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ



देहरादून, (संवाददाता) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गुप्तकाशी में चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री

ने घोषणा की कि सीमांत क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं के विस्तार हेतु राज्य में सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत जनपदों में

अब ऐसे नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहाँ आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी उपयोगी जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव के राज्य स्तरीय आयोजन का दीप प्रज्वलित शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न जनपदों से आए बाल वैज्ञानिकों के साथ जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक जल संसाधन एवं संरक्षण, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भव्य आयोजन से सीमांत जनपदों के प्रतिभावान बाल वैज्ञानिकों को नई दिशा और अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत नवाचार, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। नए भारत की गति और दिशा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

के नवाचारों पर निर्भर करेगी। विज्ञान की नई तकनीकों के बल पर आज भारत अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहा है। देहरादून में देश की पाँचवीं साइंस सिटी बनने जा रही है, जो उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जनता को पारदर्शी और प्रभावी सेवाएँ मिलें, इसके लिए अधिकांश सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर रुद्रप्रयाग जिले में आपदा प्रबंधन केंद्र के निर्माण के लिए जिलाधिकारी को कार्ययोजना बनाने के निर्देश देने के साथ ही पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बणसू जाखधार में विभिन्न कार्यों के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, सीमांत क्षेत्र के उद्यमी इंद्र सिंह रावत और सीमांत सेवा फाउंडेशन के डॉ. पाटनी को सम्मानित करने के साथ ही यूकॉस्ट की रुद्रप्रयाग डैशबोर्ड पुस्तक का विमोचन

भी किया। इस जीआईएस आधारित रिमोट सिस्टम डैशबोर्ड पर विभिन्न विभागों की योजनाओं से जुड़ी सूचनाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।

चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव की थीम – जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियाँ तथा आपदा जोखिम प्रबंधन एकीकरण है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक जल संसाधन एवं संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देना और ऐसी रणनीतियाँ विकसित करना है।

कार्यक्रम में विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग पूनम कठैत, उपाध्यक्ष महिला बाल विकास ऐश्वर्या रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष भारत भूषण भट्ट, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, जिलाधिकारी प्रतीक जैन, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा, प्रधानाचार्य पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जाखधार तिलक सिंह सहित अनेक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

पटाखों की दुकान के लिए जिला प्रशासन से अस्थाई लाइसेंस लेना होगा जरूरी



हरिद्वार (संवाददाता) । दीपावली त्योहार को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने तथा पटाखों की दुकान लगाए जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले अस्थाई लाइसेंस चिन्हित किए गए स्थानों पर ही दुकानें लगाए जाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में नगर मजिस्ट्रेट कुशम चौहान की अध्यक्षता में नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय कक्ष में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट कुशम चौहान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि दीपावली के अवसर पर लगाई जाने वाली अस्थाई पटाखों की दुकानों के लिए सभी को लाइसेंस लेने के लिए नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय एवं संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी कार्यालय में लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए कहा गया, इसके लिए सभी व्यापारी बंधुओं को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि जो भी व्यापारी पटाखों की दुकानें लगाना चाहते हैं उनके पास प्रशासन

द्वारा जारी किया गया अस्थाई लाइसेंस अनिवार्य रूप से हो।

यह निर्देश दिए

बिना लाइसेंस के पटाखों की दुकान लगाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

पटाखों की दुकानों खुले स्थानों एवं प्रशासन द्वारा पूर्व ने चिन्हित किए गए स्थानों पर ही

लगाने के निर्देश दिए।

पटाखों की दुकानों पर किसी भी तरह से ज्वलंत प्रदार्थ न रखा जाए तथा किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना न होने पाए उन्होंने कहा कि संकरी गलियों एवं तंग स्थानों पर पटाखों की दुकान न लगाई जाए, जहां फायर सर्विस का वाहन न जा सके।

पटाखों की दुकानों को निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार ही संचालित करने की निर्देश दिए। उन्होंने सभी व्यापारी से भी अपेक्षा की है कि दुकानों के आगे फुटपाथ एवं नालियों के ऊपर किसी भी तरह से कोई अतिक्रमण न किया जाए तथा सभी लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें इसके लिए उन्होंने सभी व्यापारी को डस्टबिन रखने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम को भी निर्देश दिए हैं कि नगर क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए सभी क्षेत्रों में रात्रि के समय बेहतर साफ सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, साथ ही नगर क्षेत्रगत जो भी स्ट्रीट लाइट खराब हैं उन्हें तत्परता से बदलने की निर्देश

दिए गए। उन्होंने फायर सर्विस एवं जल संस्थान को निर्देश दिए हैं कि शहर में संचालित हो रहे एवं बंद पड़े हाईड्रेंट का सयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए तथा जो हाईड्रेंट कार्य नहीं कर रहे हैं उनको दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने विद्युत विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि दीपावली के पर्व पर किसी भी तरह से विद्युत आपूर्ति बाधित न हो तथा किसी भी तरह से विद्युत लाइन में फॉल्ट आने पर तत्परता से मरम्मत कार्य करते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारू की जाए। दीपावली के अवसर पर पटाखे की बिक्री हेतु प्रशासन द्वारा चिन्हित किए क्षेत्र पंतद्वीप मैदान, रोडीबेलवाला, सूखी नदी, मायादेवी प्रांगण, मायादेवी रामलीला मैदान, ललतारौ पुल मैदान, बिल्केश्वर कुंभ मेला पार्किंग स्थल, ऋषिकुल मैदान, भल्ला कालेज की सड़क टाऊन हॉल, एस डी कॉलेज कनखल, दक्ष मन्दिर प्रांगण कनखल, बड़ा अखाड़ा शमशान घाट रोड कनखल, जगजीतपुर फुटबॉल मैदान, पुल जटवाड़ा ज्वालापुर, इंटर कॉलेज ज्वालापुर, सेक्टर - 4 पीठ बाजार भेल, चिन्मय डिग्री कॉलेज मैदान शामिल है। बैठक में सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव, अधिशासी अभियंता विद्युत दीपक सैनी, एसएनए नगर निगम ऋषभ उनियाल, व्यापार मंडल के पदाधिकारी संजीव नैय्यर, प्रदीप कालरा, राम अरोड़ा, संदीप शर्मा, राजेश पूरी, विकी तनेजा, अमन शर्मा, सहित व्यापार मंडल के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

पैसों के लेन-देन में ले ली जिगरी दोस्त की जान

– शराब पीने के बाद पैसों को लेकर हुआ विवाद, थप्पड़ का बदला लेने के लिए बेरहमी से की थी दोस्त की हत्या



हरिद्वार (संवाददाता) । हरिद्वार

के बहादुराबाद कस्बे में 1200 रुपए के लेन-देन में एक युवक ने अपने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है दोनों घनिष्ठ मित्र थे और अक्सर साथ में ही घूमते थे।

पुलिस के मुताबिक रविवार रात 24 वर्षीय सौरभ पुत्र राजाराम घर पर मौजूद था। उसी दौरान मोहल्ले में ही रहने वाला 25 वर्षीय रोहित पुत्र मांगेराम घर में घुस आया। दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर बहस हुई। इसी बीच रोहित ने चाकू निकाल लिया और सौरभ पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। शोर सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले गए। नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। वहां देर रात उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सौरभ के चाचा विवेक कुमार ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। थाना प्रभारी बहादुराबाद अंकुर शर्मा ने बताया कि जांच में पता चला है कि छोटी-छोटी चोरी कर नशा करते थे लेकिन कभी पुलिस के हथ्थे नहीं चढ़े थे। लोगों के अनुसार सौरभ और रोहित घनिष्ठ मित्र थे। दोनों अक्सर साथ ही नजर आते थे। पूछताछ में आरोपी रोहित ने बताया कि 12 अक्टूबर की शाम वह अपने दोस्त मृतक सौरभ के साथ महाडी स्थित देशी शराब के ठेके पर गए। यहां पर वे शराब पीने के बाद वापस अंबेडकर नगर मार्केट बहादुराबाद आए। यहां दोनों के बीच 1200 रुपये के लेन देन को लेकर आपस में गाली-गलौज व हाथापाई हो गई थी। जिसमें मृतक सौरभ ने उसको थप्पड़ मार दिया।

सम्पादकीय



होगी एक नई शुरुआत

कई चरणों में मतदान आम चलन बना हुआ है। मगर साथ ही यह धारणा भी मजबूत हुई है कि इस तरह चुनाव को अत्यधिक खर्चीला बनाया गया है, जिससे कम संसाधन वाले दलों के लिए प्रतिकूल स्थितियां बनी हैं। बिहार के राजनीतिक दलों में बनी यह सहमति महत्त्वपूर्ण है कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक या अधिक से अधिक दो चरणों में कराया जाना चाहिए। निर्वाचन आयुक्तों के साथ बैठक में इन दलों ने यह राय दो-टूक लहजे में बताई। उनका यह तर्क गौरतलब है कि राज्य में ना तो कानून-व्यवस्था की कोई समस्या है और ना ही अब पहले जैसे नक्सल ग्रस्त इलाके हैं, जिन्हें तर्क बना कर अनेक चरणों में मतदान कराने की शुरुआत की गई थी। हालांकि 1990 के दशक में जब यह शुरुआत हुई, तब भी इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठे थे, लेकिन तब प्रभु वर्ग में बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर एक खास तरह का प्रतिक्रिया भाव था, जिससे आयोग इस योजना को अमली जामा पहना सका। कई चरणों में मतदान धीरे-धीरे देश के अनेक हिस्सों में आम चलन बन गया। मगर साथ ही यह धारणा भी मजबूत हुई है कि इस तरह चुनाव को अत्यधिक खर्चीला बनाया गया है, जिससे कम संसाधन वाले दलों के लिए प्रतिकूल स्थितियां बनी हैं। जबकि यह सत्ताधारी दलों के अनुकूल रहा है। अच्छी बात है कि केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दलों की बिहार की ईकाइयों ने भी निर्वाचन आयोग के सामने कहा कि एक या दो चरणों में चुनाव करवा कर दलों एवं उम्मीदवारों को अतिरिक्त खर्च के बोझ से बचाया जा सकता है। खर्च के अलावा हाल में एक दूसरी समस्या भी खड़ी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के रख-रखाव और उस दौरान कथित हेरफेर की शिकायतों का फैलना अब हर चुनाव की कहानी बन गया है। इस संबंध में मतदान से लेकर मतगणना के दिन तक सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं छायी रहती हैं। इसका भी समाधान मतदान के बाद यथाशीघ्र गणना ही है। वैसे भी वोट डालने के बाद हफ्तों या कई बार महीने भर से भी ज्यादा तक परिणाम का इंतजार करना विसंगति भरा अहसास देता है। इसलिए बिहार के दलों ने जो कहा है, निर्वाचन आयोग को अवश्य ही उसके अनुरूप चुनाव कार्यक्रम घोषित करना चाहिए। इससे एक नई शुरुआत होगी, जिसे देश भर में अपनाया जा सकेगा।

भारत की पहचान भगदड़ भी है!

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-नेता विजय की राजनीतिक रैली में 41 लोगों की मौत हुई। ऐसे हादसों की सूची लंबी है लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि एक के बाद एक हादसों से हमने क्या सीखा? क्या ऐसे हादसे कभी कम होंगे? 2024 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। यह घटना कार्यक्रम समाप्ति के समय भीड़ के बहाव के कारण हुई, जब लोग बाबा के चरण छूने या उनकी चरण रज लेने के लिए उमड़ पड़े। भारत, दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला वह देश है जहां धार्मिक उत्सव, राजनीतिक रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रीय शर्म का कारण बनते हैं। हाल के वर्षों की कई घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि प्रशासनिक लापरवाही, अपर्याप्त योजना और बुनियादी ढांचे की कमी में कैसे निर्दोष लोगों की जान जाती है। सितंबर 2025 में तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-नेता विजय की राजनीतिक रैली में 41 लोगों की मौत हो गई, जब देरी से पहुंचे काफिले को देखने के लिए लोग सड़क पर उमड़ पड़े। भगदड़ के हादसों की सूची बहुत लंबी है लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि एक के बाद एक हादसों से हमने क्या सीखा? क्या ऐसे हादसे कभी कम होंगे? 2024 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। यह घटना कार्यक्रम समाप्ति के समय भीड़ के बहाव के कारण हुई, जब लोग बाबा के चरण छूने या उनकी चरण रज लेने के लिए उमड़ पड़े। इसी तरह, 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ मेला में 'मौनी अमावस्या' के दिन पवित्र नदी में स्नान के दौरान हुई भगदड़ ने 30 लोगों की जान ले ली और 60 से अधिक घायल हो गए। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि भारत अपनी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बार-बार असफल हो रहा है। इन घटनाओं पर शासन और प्रशासन इतना गंभीर क्यों नहीं दिखाई देता? हाल के वर्षों में भारत में भगदड़ की घटनाएं एक चक्रव्यूह की तरह घूम रही हैं। 2024 के दिसंबर में हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा 2' फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। 2025 की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शन के टोकन वितरण के समय छह भक्तों की मौत हो गई, जब हजारों लोग टोकन के लिए उमड़ पड़े। फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज पर हुई भगदड़ ने कई जानें लीं। बेंगलुरु में क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की आईपीएल विजय परेड के दौरान 11 लोगों की मौत हुई, जहां प्रशासन ने भीड़ का अनुमान लगाने में चूक की। बिहार के बाबा सिद्धनाथ मंदिर में अगस्त 2024 की भगदड़ में सात मौतें हुईं। ये घटनाएं धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों में ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशनों और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी हो रही हैं। 1954 से 2012 तक भारत में 79% भगदड़ें धार्मिक आयोजनों के दौरान हुईं, जो आज भी जारी है।

अजीत द्विवेदी

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के असली सर्वोच्च नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए? यह बड़ा सवाल है क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं उस पर सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से सवाल उठाया जाता है और सोशल मीडिया में सक्रिय भाजपा के इकोसिस्टम व कथित पत्रकारों की ओर से भी सवाल उठाया जाता है। वे युवाओं की बात करते हैं तो कहा जाता है कि युवाओं को उकसा रहे हैं। वे लद्दाख के आंदोलन का समर्थन करते हैं तो कहा जाता है कि देश तोड़ने वालों के साथ हैं। विदेश में जाकर भाषण देते हैं और मौजूदा सरकार की कमियां गिनाते हैं तो उन पर विदेश में जाकर देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया जाता है। वे 'वोट चोरी' के आरोप लगाते हैं और मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हैं तो कहा जाता है कि वे संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। वे क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा उठाते हैं तो कहा जाता है कि वे देश में आर्थिक तरक्की नहीं चाहते हैं और देश को पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं इसलिए उद्योगपतियों पर सवाल उठा रहे हैं। आदि, आदि।

वास्तविकता यह है कि इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता होने और लोकसभा में नेता विपक्ष होने के नाते उनको नहीं करना चाहिए। वे वही काम कर रहे हैं, जो करने की जिम्मेदारी उनको देश के नागरिकों ने दी है। ध्यान रहे देश के मतदाता सिर्फ सरकार नहीं चुनते हैं, बल्कि विपक्ष भी चुनते हैं। उन्होंने 2014 और 2019 में कमजोर विपक्ष चुना और मजबूत सरकार चुनी। लेकिन 2024 में कमजोर सरकार और मजबूत विपक्ष चुना। देश के सौ करोड़ मतदाताओं के जनादेश से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। जैसे प्रधानमंत्री जनता की ओर से दी गई जिम्मेदारी निभा रहे हैं वैसे ही राहुल गांधी भी मतदाताओं द्वारा की गई जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

हां, यह जरूर है कि वे इस जिम्मेदारी को और बेहतर ढंग से निभा सकते थे। उनके पास अब 21 साल का राजनीतिक और विधायी कामकाज का अनुभव है। इसमें से 10 साल उनकी पार्टी सरकार में रही तो निश्चित रूप से सरकार के कामकाज भी उनकी भूमिका रही। सो, वे सरकारी कामकाज के तौर तरीकों से परिचित हैं तो 11 साल की विपक्ष की राजनीति करके वे विपक्ष की भूमिका से भी बखूबी परिचित हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर काम करते देखा है। उन्हें यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या वे उस तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जैसे भाजपा ने 2004 से 2014 के बीच निभाई थी? विपक्ष की भूमिका से आशय संसद के अंदर के कामकाज से नहीं है। वहां तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां भी वैसे ही संसद स्थगित कर रही हैं, हंगामे और नारेबाजी कर रही हैं, जैसे भाजपा करती थी। लेकिन संसद के बाहर और मीडिया स्पेस में जिस तरह से भाजपा ने काम किया वह विपक्ष की टेक्स्टबुक भूमिका थी। कांग्रेस के सरकार में होने के बावजूद भाजपा ने कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार और महंगाई तक अपना नैरेटिव बनाया और कांग्रेस सारे समय उसका जवाब देती रही।



इसके उलट आज जब राहुल गांधी और कांग्रेस विपक्ष में हैं तब भी भाजपा और सरकार ही नैरेटिव बना रहे हैं और कांग्रेस उनका जवाब दे रही है। यानी विपक्ष में होकर भी कांग्रेस रिसीविंग मोड में है। यह भाजपा के नैरेटिव की ताकत है, उसकी होशियारी, अति सक्रियता और संसाधनों की बहुतायत है या कांग्रेस की कमजोरी है यह अलग बहस का विषय है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले 11 साल में एकाध मौकों को छोड़ दें तो कांग्रेस कभी भी सरकार को घेरने, उसे बैकफुट पर लाने और उसको जवाबदेह बनाने वाले नैरेटिव के सेंटर में नहीं रही। ज्यादातर मौकों पर अराजनीतिक समूहों ने सरकार को जवाबदेह बनाया। कांग्रेस को इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर वह क्यों बहुत प्रभावी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। उसे इस पर भी सोचना चाहिए कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगातार एंटी इन्कम्बेंसी को कम करने या बढ़ने नहीं देने के लिए काम कर रहे हैं।

बहरहाल, विषयांतर हो रहा है लेकिन मूल बात यह है कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं, जो देश के नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको करना चाहिए। राहुल गांधी अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और उसकी निष्ठा संदिग्ध बता रहे हैं तो वे ऐसा करने वाले पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी तो उसके नेता भी चुनाव आयोग पर, चुनाव प्रक्रिया पर और ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे और उनके करीबी जीवीएल नरसिंहराव ने इस पर किताब लिखी थी। बाद में जीवीएल को राज्यसभा भेजा गया था। उससे भी बहुत पहले जब बैलेट से चुनाव होता था आडवाणी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था इंदिरा गांधी ने बैलेट पर ठप्पा लगाने वाली स्याही रूस से मंगाई है, जो मिट जाती है। सो, आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में और मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ कर रहा है तो यह विपक्ष के नेता का स्वाभाविक आरोप है।

ऐसे ही राहुल गांधी जब 'जेन जी' यानी 13 साल से लेकर 28 साल तक के युवाओं की बात करते हैं और कहते हैं कि उनको 'वोट चोरी' की असलियत का यकीन हो गया तो वे बरदाश्त नहीं करेंगे। इस पर भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी युवाओं को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी तख्तापलट के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले विपक्षी नेताओं ने इस तरह की बात नहीं की है

या तख्तापलट की अपील नहीं की है। तमाम समाजवादी नेता आज भी राममनोहर लोहिया की इस बात को दोहराते हैं कि, 'जिंदा कौमें पांच साल तक इंतजार नहीं करतीं'। यहां तो लोहिया साफ साफ लोगों को बगावत के लिए उकसाते दिख रहे हैं लेकिन उनके इस बयान को स्वाभाविक लोकतांत्रिक भावना के तौर पर देखा गया। ऐसे ही जयप्रकाश नारायण ने जब सेना और पुलिस से अपील की थी कि वे सरकार के साथ असहयोग करें तो तब की कांग्रेस सरकार ने यही कहा था कि वे सेना और पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन तब से लेकर आज तक यही माना जाता है कि जेपी लोकतंत्र की रक्षा कर रहे थे। सो, अगर डॉक्टर लोहिया और जेपी गलत नहीं थे तो राहुल कैसे गलत हैं?

जहां तक विदेश जाकर सरकार के खिलाफ बोलने का सवाल है तो इसका भी लंबा इतिहास रहा है। खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विदेशी धरती पर जाकर अपने से पहले वाली सरकारों के कामकाज की खूब आलोचना की। एक बार तो वे भवावेश में यहां तक कह गए थे कि 2014 से पहले लोगों को शर्म आती थी कि कहां से भारत में पैदा हो गए। यह बात मोदी ने विदेश में ही कही थी। उससे बहुत पहले जब संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब सुब्रह्मण्यम स्वामी भी विदेश जाकर भारत सरकार के खिलाफ समर्थन जुटा रहे थे तो जेल में बंद जॉर्ज फर्नांडीज की पत्नी लैला कबीर भी विदेश जाकर उनकी रिहाई का आंदोलन चला रही थीं। सो, विदेश जाकर अपने देश की सरकार के कामकाज की आलोचना करना देश का अपमान नहीं होता है।

अब रही बात जन आंदोलनों का समर्थन करने की तो यह सबसे हैरान करने वाली बात है कि आंदोलनों से बनी और दशकों तक लगातार विपक्ष में रह कर आंदोलन खड़ा करने वाली भारतीय जनसंघ और भाजपा के नेता कैसे आंदोलन के समर्थन को देश विरोध बता सकते हैं? राहुल ने किसान आंदोलन का समर्थन किया या सीएए के खिलाफ हुए आंदोलन का समर्थन किया या लद्दाख के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सभी लोकतांत्रिक आंदोलन थे, जो इस देश के नागरिकों ने अपने अधिकार के लिए चलाए थे।

यह सरकार का जिम्मा होता है कि वह आंदोलन करने वालों से बात करे, उनकी मांगें सुने और उसका समाधान करे। विपक्ष तो ऐसे आंदोलन का समर्थन करेगा ही। अफसोस की बात है कि खुद कांग्रेस और राहुल गांधी कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने और उससे पहले भारतीय जनसंघ ने अनेक आंदोलन खड़े किए। जेपी का आंदोलन भी उनमें से एक था। याद करें आजादी के बाद इस देश में कितने आंदोलन हुए। भाषा के आंदोलन, मंदिर का आंदोलन, सत्ता बदलने का आंदोलन, नए राज्यों का आंदोलन, क्या उस समय की सरकारों ने इन आंदोलनों में शामिल नेताओं व नागरिकों को देशद्रोही माना!

हिमालय

की गोद में बसे शहर

देहरादून में MDDA उपलब्ध करा रहा है
घर का सपना पूरा
करने का
सुनहरा अवसर

प्रस्तावित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे द्वारा दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घण्टे में संभव होगा।

आलुयम
आवासीय योजना



लोकेशन देखने हेतु
QR कोड स्कैन करें

सीमित
H.I.G 3 BHK Flats
अवशेष

Rera No. UKREP10240000585

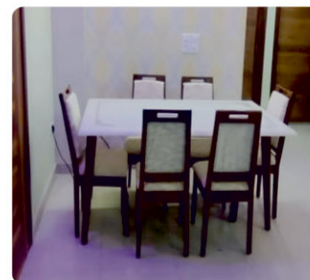
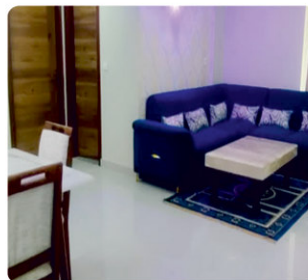
- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लाया है सहस्रधारा मुख्य मार्ग के समीप प्रकृति की गोद में स्थित आवासीय योजना।
- बुकिंग के समय 10 प्रतिशत का भुगतान, शेष 90 प्रतिशत का भुगतान एक मुश्त व एक माह में करने पर 02 प्रतिशत की छूट।
- महिला/सीनियर सिटीजन/दिव्यांग को 01 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट।

नियम और शर्तें लागू



UNIT	SUPER AREA	COVERED AREA	BSP
H.I.G. 3 BHK	1877.83 sq ft	1240.63 sq ft	75.64 Lacs
M.I.G. 2 BHK	1503.40 sq ft	980.88 sq ft	65.85 Lacs
STUDIO APARTMENT	798.18 sq ft	374.02 sq ft	32.29 Lacs
L.I.G-C Block	585.82 sq ft	409.42 sq ft	23.29 Lacs

सैंपल प्लैट की तस्वीरें



मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

सहारनपुर रोड़, ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून | PH.: 0135-663150 | E mail: info.mdda@mddaonline.in

Website : www.mddaonline.in | Mobile No.: 9012451953 8006409136

पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत

देहरादून शहर के अंतरराज्यीय बस अड्डा के पास
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपलब्ध करा रहा है
आपके सपनों का घर



M.D.D.A.
HIG Housing
Scheme
RERA Number:
UKREP09170000017



मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण आवासीय परिसर
निकट आई० एस० बी० टी०, हरिद्वार बाई पास रोड, देहरादून



आज ही अपना घर बुक करें और
2% छूट का लाभ उठाएं*

● 10% राशि बुकिंग पर और शेष 90% राशि का भुगतान एक महीने के अंदर करें।

● कुल लागत पर 2% की छूट प्राप्त करें

● महिलाओं, वृद्ध नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांगों को 1% अतिरिक्त छूट

● समस्त 10 टावर जीएसटी मुक्त

अपनी बचत सुरक्षित करें

सही निवेश का माध्यम
एम.डी.डी.ए.

: मुख्य आकर्षण :

- दिल्ली से देहरादून तक का सफर 2.5 घंटे में (प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे से)
- हवाई अड्डे तक 40 मिनट की दूरी
- व्यक्तिगत पहुंच मार्ग

- मसूरी और शिवालिक का दृश्य
- मेट्रो पास में प्रस्तावित
- पास में ट्रांसपोर्ट नगर

होम लोन सभी बैंकों से उपलब्ध है

*Conditions apply



Park Proposed



Sample Flat (actual pic)



Gym Facility (actual pic)



Pool / Snooker Facility (actual pic)



Quality Check by WAPCOS



200+ Gathering



2 Min Walk to ISBT, Mall, Multiplex



Reputed Schools within 3 KM



Fire Safety



Multi-speciality Hospital - 2 Km



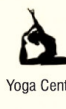
Dedicated Parking



Dedicated Water Supply & STP Plant



Gym Arcade



Yoga Centre



Pool



Park Facility



Security

Mussoorie Dehradun Development Authority

Transport Nagar, Saharanpur Road, Near I.S.B.T., Dehradun. Call: 8700733628

Email: info.mdda@mddaonline.in | Website: mddaonline.in



मौका दीजिये अपने खून को
किसी की रगो में बहने का
ये लाजवाब तरीका है
कई जिस्मों में जिंदा रहने का



प्रसारित
राज्य रक्त संचरण परिषद्
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड



अधिक जानकारी के लिए eraktkosh पोर्टल पर देखें

मौत का सिरप : जवाबदेही से भागता तंत्र !

सुनील कुमार महला

नकली दवाएं बनाना और बेचना केवल अपराध नहीं, पाप है। यह वह कुकर्म है जो जीवन देने के नाम पर मृत्यु बाँटता है। लाभ की लालसा जब संवेदनाओं पर भारी पड़ती है, तब ईसानियत मर जाती है। बीमार की आशा को छलना मानवता का सबसे बड़ा अपमान है। ऐसे स्वार्थी लोग समाज और मानवता दोनों के शत्रु हैं। दवा नहीं, जहर बनाकर वे जीवन के अधिकार का उपहास उड़ाते हैं। धन के पीछे भागता मनुष्य कब नैतिकता से इतना गिर गया? सोचिए, ऐसा स्वार्थ और लालच हमें अंततः कहाँ ले जाएगा? बहरहाल, कफ सिरप (खांसी की दवाई) सामान्यतः खांसी या जुकाम के लक्षणों को कम करने के लिए बच्चों और वयस्कों को दी जाती है, लेकिन यह बहुत ही अफसोसजनक है कि कफ सिरप में मिलावट या अशुद्धता के कारण गंभीर साइड इफेक्ट्स या मृत्यु तक हो रही हैं। इस क्रम में हाल ही में हमारे देश में कफ सिरप संबंधी शिकायतों का एक बार फिर से उठना न केवल दुःखद, बल्कि शर्मनाक भी है। इस संबंध में मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो खबरें आई हैं, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कफ सिरप के कारण कम-से-कम 9 से 12 बच्चों की मौतें हुई हैं, और इनमें से अधिकतर बच्चों में गुर्दे संबंधी समस्याएँ देखने को मिली हैं। परीक्षण में पाया कि एक कफ सिरप में डीईजी स्तर अनुमत सीमा से अधिक था। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि डायथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी)



और एथिलीन ग्लाइकोल (ईजी) औद्योगिक रसायन हैं, जिनका उपयोग अक्सर अवशुद्ध या नीचे-स्तरीय ग्लाइकोल स्रोतों में होता है। जब इन्हें दवा निर्माण में गलती से या धोखाधड़ी से शामिल कर दिया जाता है, तो ये गुर्दे (किडनी) को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकते हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज दवाओं की उत्पादन प्रक्रिया में विनिर्माण दोष जैसे कि कच्चे माल की शुद्धता की जाँच न होना, प्रोसेस कंट्रोल का नाकाफी होना, दवाओं के प्रयोग से पहले उनका ठीक ढंग से परीक्षण नहीं किया जाना, दवाओं पर लेबलिंग त्रुटियाँ और ग़लत जानकारी, कमजोर दवा विनियमन जैसे कारणों से दवाओं के हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। हाल ही में कफ सिरप के क्रम में संबंधित राज्य

को सरकार ने उस सिरप की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया, यह अच्छी बात है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में हाल ही में केंद्र ने भी बच्चों (विशेषकर 2 वर्ष से कम आयु) को बिना जाँच के कफ सिरप नहीं देने की एक एडवाइजरी भी जारी की है। बताया गया है कि बच्चों में खांसी जुकाम आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाते हैं, ऐसे में आराम, हाइड्रेशन व सहायक उपचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सामान्यतया 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी दवाओं का उपयोग नहीं करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, बड़ी उम्र के बच्चों में भी दवा केवल डॉक्टर की सलाह पर समुचित खुराक

दिए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही एक साथ कई दवाओं के कॉम्बिनेशन से बचने और दवा कम से कम अवधि तक दिए जाने तथा सभी स्वास्थ्य संस्थानों को केवल प्रमाणित गुणवत्ता वाली दवाएँ ही खरीदने हेतु कहा गया है। बहरहाल, मध्यप्रदेश और राजस्थान में अगर ये मौतें नकली या खराब कफ सिरप की वजह से हुई हैं, तो फिर दोषियों को किसी भी हाल और परिस्थितियों में छोड़ना नहीं चाहिए। वास्तव में, दोषी पाए जाने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और इस संबंध में सरकार को पारदर्शी जाँच, और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बहरहाल, कफ सिरप की शिकायत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये जेनेरिक श्रेणी की है और इसका वितरण सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए हुआ है, वास्तव में यह बहुत ही चिंताजनक व संवेदनशील है। चिंताजनक व संवेदनशील इसलिए क्योंकि कि यहां सवाल यह उठता है कि क्या हमारे यहां जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है? सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकारी स्तर पर होने वाली खरीद में नकली या फर्जी दवाओं को खपाया जा रहा है? कहना ग़लत नहीं होगा कि नकली और मिलावटी दवाएं मानव जीवन के लिए गंभीर ख़तरा हैं। इनसे रोग ठीक होने के बजाय और बढ़ सकते हैं। फर्जी दवाएँ लोगों के स्वास्थ्य और भरोसे दोनों को चोट पहुँचाती हैं। गुणवत्ता विहीन दवाओं का असर न के बराबर या हानिकारक होता है। वास्तव में, दवा निर्माण और वितरण पर कड़ी निगरानी से ही समाज और देश को सुरक्षित रखा जा सकता है। ध्यातव्य है कि आज जेनेरिक दवाओं का वितरण करने वाले औषधि केंद्रों की संख्या पूरे देश में लगातार बढ़ रही है। गौरतलब है कि भारत ने सरकार द्वारा प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सस्ते जेनेरिक दवाओं की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 तक इस योजना के तहत 10,006 दुकानें थीं और विक्रय (सेल्स) 1,470 करोड़ रही। हमारे देश में 28 फरवरी 2025 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या 15,057 थी तथा 30 जून 2025 तक कुल 16,912 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक यह केंद्रों की संख्या 25,000 हो जाए, यह काबिले-तारीफ है। जन औषधि केंद्रों के फायदे यह हैं कि इनसे देश में सस्ती दवाओं की उपलब्धता होती है। जन औषधि केंद्र भारत में निर्मित जेनेरिक दवाओं की बिक्री को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलता है। इनसे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में इजाफा होता है देश में रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन जन औषधि केंद्रों में मिलने वाली सभी दवाएँ डब्ल्यू एच ओ-जीएमपी प्रमाणित लैबों में परीक्षण के बाद ही उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि गुणवत्ता पर सवाल न उठे पाएँ। बहरहाल, कफ सिरप संबंधी शिकायतों पर राजस्थान सरकार ने मुस्तैदी से कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित दवा के 22 बैचों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यहां ध्यान देने की बात है कि सिरप की सुरक्षा साबित करने की कोशिश में एक सीनियर डॉक्टर ने दवा का सेवन किया और वे बेहोश हो गए। हालांकि, डॉक्टर के बेहोश होने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकारियों के मन में शक ने कहीं न कहीं जरूर जन्म लिया है और इस शक को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वास्तव में आज जरूरत इस बात की है देश में समय-समय पर दवाओं की गुणवत्ता, मानकों की जांच की जानी चाहिए। दवाओं के साथ खिलवाड़ से बड़ा अपराध कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज दवा निर्माण और वितरण में

पारदर्शिता व सख्त निगरानी जरूरी है, क्यों कि आज आदमी अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए दवाओं तक में मिलावट/नकली दवाओं का निर्माण, लापरवाही कर रहा है और इसके पीछे बड़े रैकेट काम कर रहे हैं। इन रैकेट्स को पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। वास्तव में, जनस्वास्थ्य की रक्षा हेतु दवाओं से जुड़ी हर लापरवाही पर कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। सच तो यह है कि ऐसे अक्षम्य अपराधियों को कतई छोड़ना नहीं चाहिए। गौरतलब है कि सीकर जिले में पांच साल के बच्चे और भरतपुर में दो साल के बच्चे की सिरप पीने से मौत हुई है। मध्य- प्रदेश में ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। यहां पाठकों को बताता चलूँ कि कफ सिरप की शिकायत का मामला तीन साल पहले भी सामने आया था। कथित रूप से अफ्रीकी देशों में भारतीय कफ सिरप की वजह से 50 से ज्यादा बच्चों की मौत बताई गई थी। उस समय भी भारत सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए थे। कहना ग़लत नहीं होगा कि उससे भी कड़े कदम उठाए जाने की आज जरूरत है। आंकड़े और रिपोर्ट्स बताती हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 (भारत सरकार द्वारा संसद में) कुल 1,16,323 ड्रग सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 3,104 दवाएँ %नोट आफ स्टैंडर्ड क्वालिटी% (एन एस क्यू) पाई गईं तथा 245 दवाएँ दोषपूर्ण / मिलावटी रहीं और इस संबंध में अभियोग (प्रोसिक्यूशन्स) की संख्या 961 रहीं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नकली दवाओं के मामले में चीन के साथ भारत का भी नाम लिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक, भारत में बेची जाने वाली 5 से 25 प्रतिशत दवाएँ नकली या घटिया हो सकती हैं। देश के जो इलाके नकली दवाओं के लिए जाने जाते हैं, वहां अब युद्ध स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। बहरहाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीड़ित बच्चों को दी गई दवाओं के सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह माना है कि उनमें डायथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी) या एथिलीन ग्लाइकोल (ईजी) जैसे घातक रसायन मौजूद नहीं हैं, जबकि मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने के कारण ही बच्चों की मौत हुई है। बीते 3 अक्टूबर को भी मध्यप्रदेश में एक बच्चे की अस्पताल में मौत हुई। बहरहाल, राजस्थान राज्य सरकार की निःशुल्क दवा योजना में सप्लाय की गई डेक्स्ट्रोमैथॉर्फन कफ सिरप को सरकार ने जांच के बाद क्लीन चिट दे दी है। हालांकि, यह सिरप बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है। सीकर और भरतपुर के तीन बच्चों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग ने कंपनी की ओर से आपूर्ति की गई दवा के सैंपलों की जांच करवाई थी, जिसमें दूषित होने व डीईजी, ईजी का संभावित स्रोत हानिकारक प्रोपाइलीन ग्लाइकोल नहीं पाया गया। इधर, छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में कफ सिरप लेने के बाद किडनी फेल होने से अस्पताल में भर्ती एक और बच्चे ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या नौ हो गई, जबकि 12 अन्य बच्चे गंभीर हालत में नागपुर और छिंदवाड़ा के अस्पतालों में मौत से संघर्ष कर रहे हैं। सभी बच्चों की उम्र 5 वर्ष से कम है। मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार मृत बच्चों के घर से कोल्ट्रिफ और नेक्सट्रांस-डीएस सिरप मिले थे। मध्यप्रदेश में कफ सिरप लेने के बाद किडनी फेल होने से नौ बच्चों की मौत के बाद दवा सैंपल की लेबोरेटरी जांच को लेकर विरोधाभास भी सामने आया। केंद्र सरकार ने कहा है कि मध्यप्रदेश में मरने वाले बच्चों के पास मिली दवा के सैंपल की जांच में प्रतिबंधित घातक रसायन डीईजी/ईजी की पुष्टि नहीं हुई है।



(2 अक्टूबर, 1869 – 30 जनवरी, 1948)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

को उनकी जयंती पर

शत शत नमन

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

www.uttarainformation.gov.in
[uttarakhandDIPR](https://twitter.com/uttarakhandDIPR)
[DIPR_UK](https://www.facebook.com/uttarakhandDIPR)
[uttarakhand DIPR](https://www.youtube.com/uttarakhandDIPR)

कांतारा-चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज, ऋषभ शेट्टी के खूंखार अवतार ने फिर उड़ाए होश



साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक ऋषभ शेट्टी स्टार कांतारा-चैप्टर 1 अपनी रिलीज का इंतजार कर रही है। फिल्म को रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले कांतारा का सीकल देख चुके दर्शकों को इसके प्रीकल (कांतारा-चैप्टर 1) के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था, जो खत्म हो चुका है। कांतारा-चैप्टर 1 के मेकर्स होम्बले ने बीते दिन एक पोस्ट जारी कर बताया था कि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा। अब फिल्म मेकर्स ने कांतारा-चैप्टर 1 का इंतजार कर रहे हिंदी पट्टी के दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल गया है। दरअसल, कांतारा-चैप्टर 1 का हिंदी ट्रेलर बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने लॉन्च कर दिया है।

होम्बले ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी थी। होम्बले फिल्म ने अपने एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया था, जिसमें फिल्म कांतारा-चैप्टर 1 के पोस्टर पर ऋतिक रोशन की झलक दिख रही थी। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, जब दो सुपरस्टार की मुलाकात होती है, कांतारा-चैप्टर 1 का हिंदी ट्रेलर शानदार एक्टर ऋतिक रोशन लॉन्च करेंगे, ज्यादा लेजेंड्स और ज्यादा भाषाएं, कांतारा-चैप्टर 1 पूरी दुनिया में दहाड़ेगी, फिल्म की ट्रेलर 22 सितंबर दोपहर 12.45 बजे रिलीज होगा और 22 सितंबर को तय समय से ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसकी टैगलाइन में लिखा है, ट्रेलर कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जातीं, जी जाती हैं।

लगभग तीन मिनट के ट्रेलर में शानदार कहानी और अद्भुत विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। इसकी शुरुआत शिव के पुत्र के उसी स्थान पर पहुंचने से होती है, जहां उसके पिता जंगल में विलीन होकर अग्नि के गोले में खो गए थे, कांतारा-चैप्टर 1 का ट्रेलर एक क्लासिक अच्छाई बनाम बुराई के संघर्ष की ओर इशारा करता है। यह उत्पीड़कों के विरुद्ध उत्पीड़कों के संघर्ष को दर्शाता है। इसके अलावा, यह एक चेतावनी भरी कहानी भी पेश करता है कि कैसे लालच सब कुछ नष्ट कर सकता है, यह प्रकृति, लोककथाओं और ईश्वर के साथ मानवीय संबंधों को एक साथ बुनता है, जिससे उस दुनिया की एक

झलक मिलती है जिसमें फिल्म की पृष्ठभूमि है। ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि कांतारा-चैप्टर 1 अपनी चर्चाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। होम्बले फिल्म की यह फिल्म भूत कोला अनुष्ठान की प्राचीन उत्पत्ति पर बेस्ड है, जिसे एक बार फिर ऋषभ शेट्टी ने जीवंत किया है, जो फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं और उन्होंने फिल्म का सह-लेखन और निर्देशन भी किया है। प्रीकल का महत्व और भी व्यापक है, क्योंकि यह होम्बले की महत्वाकांक्षी पांच वर्षीय योजना का हिस्सा है, जिसमें बेंगलुरु स्थित इस स्टूडियो ने चार दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया है। बता दें, साल 2022 में जो कांतारा

रिलीज हुई थी, वह फिल्म का सीकल थी, अब फिल्म का प्रीकल रिलीज होगा। यानि फिल्म कांतारा-चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी अपने किरदार की पिछली कहानियों के बारे में बताएंगे और साथ ही फिल्म में यह देखने को मिलेगा कि उनके पिता जो जंगल में पूजा करने गए थे, वो कैसे गायब हुए और कैसे उन्हें एक शक्ति ने अपनी जद में ले लिया था। साथ ही फिल्म यह खुलासा होगा कि कैसे एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके शरीर में प्रवेश कर बुरे लोगों का सर्वनाश करता है। फिल्म कांतारा-चैप्टर 1 आगामी 2 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज होगी।

मर्दानी 3 का नया पोस्टर जारी, शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में लौट रहीं रानी मुखर्जी



रानी मुखर्जी मर्दानी 3 में शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोनों इंस्टालमेंट की सफलता के बाद मेकर्स ने तीसरे भाग की रिलीज की तारीख 27 फरवरी, 2026 को तय की है। नवरात्रि के पावन अवसर पर, मेकर्स ने मर्दानी 3 का नया पोस्टर जारी किया। नवरात्रि के पहले दिन यशराज फिल्म ने इंस्टाग्राम पर मर्दानी 3 का नया पोस्टर जारी किया है। इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, नवरात्रि के पावन पहले दिन, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हुए, रानी मुखर्जी अपने करियर के सबसे चैलेंजिंग केस की जांच करने के लिए मर्दानी 3 में टॉप पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में लौट आई हैं। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 27 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी। पोस्टर की बात करें तो पोस्टर में रानी का क्लोज-अप दिखाया गया है, जिसमें वह एक ब्लैक कलर रंग का गन पकड़े हुए नीचे की ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्लर बैकग्राउंड में एक पीले रंग का पुलिस बैरिकेड दिखाई दे रहा है जिस पर दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है। इस पोस्टर के साथ रानी मुखर्जी अच्छाई और बुराई के बीच एक नए युद्ध के लिए तैयार लग रही हैं। रानी मुखर्जी ने पहले खुलासा किया था कि यह रोमांचक फिल्म डार्क, जानलेवा और क्रूर होगा। इस खुलासे के बाद से फैंस के बीच बज बना हुआ है। मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मोनावाला ने किया है। तीसरी इंस्टालमेंट में रानी की निडर पुलिसकर्मी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी हुई है, जो न्याय के लिए लड़ती है। यशराज फिल्म की निर्मित मर्दानी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी एकल महिला-प्रधान फ्रैंचाइजी है, जो 11 साल पहले शुरू हुई थी। इस फिल्म फ्रैंचाइजी ने अपनी दमदार कहानी के लिए तब से प्यार और प्रशंसा बटोरी है। इस ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी को लोगों का भरपूर प्यार मिला है और इसने सिनेमा प्रेमियों के बीच एक कल्ट का दर्जा हासिल कर लिया है। 2014 में रिलीज हुई मर्दानी का निर्देशन प्रदीप सरकार ने किया था। दूसरी किस्त का निर्देशन गोपी पुश्तान ने किया था, जिन्होंने फिल्म फ्रैंचाइजी का पहला भाग लिखा था। जहां, मर्दानी मानव तस्करी की कहानी पर आधारित थी, वहीं 2019 में रिलीज हुई मर्दानी 2 एक मनोरोगी, बलात्कारी और हत्यारे की कहानी पर आधारित थी।

इमरान हाशमी और यामी गौतम की हक का पहला पोस्टर आया सामने, आज रिलीज होगा टीजर?

अभिनेत्री यामी गौतम पिछले काफी समय से अपनी आगामी फिल्म हक को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसके निर्देशन की कमान सुप्रण वर्मा ने संभाली है। इस फिल्म में यामी के साथ अभिनेता इमरान हाशमी नजर आएंगे और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। अब निर्माताओं ने हक का पहला पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें यामी का दमदार लुक दिख रहा है। हालांकि, पोस्टर में उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। हक का टीजर 23 सितंबर, 2025 को रिलीज किया जाएगा। निर्माताओं ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, घर की दहलीज से सुप्रीम कोर्ट तक... हक और उस हक की लड़ाई। टीजर कल आ रहा है। इस फिल्म की कहानी एक ऐतिहासिक कानूनी मामले पर आधारित है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।



अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस, आकर्षक व्यक्तित्व और अनुशासित जीवनशैली के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने

पीला, हरा, लाल और नीला रंग से सजा हुआ है, जिसमें सुनहरी जरी का वर्क हुआ है। चोली पर बारीक कढ़ाई ने उनके स्लिम फिगर को

शनिवार को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर त्योहारों के आगमन की खुशी जताई है। शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह कई तरह के पोज देती नजर आ रही हैं। कैमरे के सामने उनका हर अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है। कभी वह हल्की-सी स्माइल के साथ पोज दे रही हैं, तो कभी गोल घूमकर तरह-तरह के पोज दे रही हैं। अभिनेत्री ने पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, इस त्योहार के मौसम के लिए एक रंग काफी नहीं है। लुक की बात करें तो शिल्पा ने मल्टीकलर का घाघरा-चोली पहन रखा है। यह घाघरा

और निखारा है, जो उनकी फिटनेस रूटीन का प्रमाण देता है। बालों को उन्होंने हाफ चोटी में बांधा है, जिस पर रंग-बिरंगे रिबन लहरा रहे हैं। चेहरे पर उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है। वहीं, अभिनेत्री ने इस वीडियो के साथ गुजराती गाना रमति आवे को ऐड किया है। उनका यह पोस्ट देख फैंस को गरबा की याद दिला रहा है, जिसमें हर ट्विस्ट और टर्न होने से रंग बिखरे लग रहे हैं। शिल्पा शेट्टी के पोस्ट करते ही वीडियो में लाखों व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं। एक यूजर ने लिखा, कभी नवरात्रि खेलने आओ वडोदरा, तो दूसरे यूजर ने लिखा, गरबा क्वीन, और एक और यूजर ने लिखा, मैम, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। गाने की बात करें तो रमति आवे एक गुजराती गाना है, जिसका नाम डाकला-2 है। यह एक तरह का गरबा सॉन्ग है और नवरात्रि के आगमन के पहले से ही ये सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। शिल्पा शेट्टी को आखिरी बार फिल्म सुखी में देखा गया था। वो बहुत जल्द कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म केडी-द डेविल में नजर आएंगी। इसमें संजय दत्त, ध्रुव सरजा और नोरा फतेही भी अहम किरदार में हैं।

गंगा तट से गाँव तक स्वच्छता, स्वास्थ्य और समृद्धि से गढ़ती हरिद्वार की नई पहचान

हरिद्वार (संवाददाता) । । पावन नगरी हरिद्वार में आयोजित स्वच्छोत्सव पखवाड़ा केवल स्वच्छता का पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, सामाजिक और स्वास्थ्य जनांदोलन बनकर सामने आया। "स्वच्छता ही सेवा" पखवाड़े के अंतर्गत, आईटीसी मिशन सुनहरा कल और श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने मिलकर मंदिर स्वच्छता, गंगा घाट सफाई, स्वास्थ्य शिविर, जन-जागरूकता रैलियाँ और नुककड़ नाटक जैसे विविध कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे समाज में नई चेतना का संचार किया। कनखल के प्राचीन हनुमानगढ़ी, दक्षेश्वर महादेव, चंडीदेवी और मनसा देवी मंदिर, हरकी पौड़ी अब स्वच्छता और भित्ति-चित्रों से सजे एक आध्यात्मिक सौंदर्य के प्रतीक बन चुके हैं। आईटीसी मिशन सुनहरा कल और श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम का यह अभिनव प्रयास अनुकरणीय है। मंदिरों से निकले पुष्पों का गंगा में विसर्जन रोककर उनका खाद एवं धूपबत्ती में उपयोग वास्तव में दिव्य और उपयोगी पहल है। कांवड़ पर्व के बाद शिव घाट, विष्णु घाट और दक्ष घाट पर जिला प्रशासन, नगर विधायक मदन कौशिक जी, रानीपुर विधायक श्री आदेश चौहान जी व आईटीसी मिशन सुनहरा कल के संयुक्त प्रयास से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंदिरों से निकले निरमाल्य पुष्पों को धूप अगरबत्ती बनाने हेतु सरस केंद्र, जमालपुर कला भेजा गया। महिला समूहों व आकांक्षा दिव्यांग विद्यालय, भेल के दिव्यांग छात्र-छात्राओं ने इन्हें धूपबत्ती व अगरबत्ती में परिवर्तित किया। इस पहल से न केवल गंगा प्रदूषण में कमी आई बल्कि पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए।

मिस्सरपुर में हाथियों की आवाजाही पर लगे रोक

हरिद्वार (संवाददाता) । पथरी के मिस्सरपुर की आवासीय कॉलोनी में हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। रविवार सुबह आठ बजे हाथियों का झुंड कॉलोनी में घुसा और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों और गमलों को नुकसान पहुंचाया। यह देख क्षेत्रवासी भी दहशत में आ गए। ग्रामीणों का कहना है कि इन दिनों मिस्सरपुर, बहादुरपुर जट, किशनपुर, गाडोवाली, पंजनहेड़ी, अजीतपुर, जियापोता, कटारपुर, चांदपुर, रानीमाजरा, बिशनपुर व पुरानी कुंडी में हाथियों की आवाजाही बनी हुई है। हाथी कॉलोनी से होते हुए खेतों में घुस कर गन्ने की फसल का नुकसान पहुंचाते हैं। किसान राजेश सैनी, किसान अब्दुल सलाम, नूतन कुमार, सुशील सैनी, सुखदेव पाल, ब्रजपाल, राजपाल, सुनील, राजबीर, दीपक, रमेश, सोनी आदि किसानों का कहना है कि दिन छिपते ही हाथियों का झुंड पहले कई दिनों से मिस्सरपुर आवासीय कॉलोनी और पास ही खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं।

डीएम और जिला जज ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ

हरिद्वार (संवाददाता) । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के तत्वावधान में रविवार को नशा उन्मूलन और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र दत्त ने की। ऋषिकुल मैदान पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और जिला न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने जनसमूह को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश और एसपी सिटी जितेंद्र मेहरा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इनर व्हील क्लब, बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बाल संरक्षण विभाग, मेडिकल और लॉ कॉलेजों, सरकारी व निजी विद्यालयों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। युवाओं ने 'नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो और 'स्वस्थ समाज की यही पहचान, नशा मुक्त हो देश महान जैसे नारे लगाकर जागरूकता का संदेश दिया। रैली ऋषिकुल मैदान से शुरू होकर चंद्राचार्य चौक होते हुए गोविंद घाट पर समाप्त हुई, जहां प्रतिभागियों ने गंगा तट पर स्वच्छता अभियान चलाया। समापन अवसर पर जिला न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और इसे समाप्त करने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। युवाओं को नशे से दूर रहकर दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि नशा मुक्ति की दिशा में यह पहल हरिद्वार को नई सोच और दिशा देगी। अंत में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार सिविल जज सीनियर डिबीजन सिमरनजीत कौर ने सभी प्रतिभागियों, विभागीय अधिकारियों और सहयोगी संस्थाओं का आभार जताया। रैली में अपर जिला जज अंजूश्री जुयाल, राकेश कुमार सिंह, राजू कुमार श्रीवास्तव, चंद्रमणि राय, अरुण वोहरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि बंसल, विभा यादव, अविनाश कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी जितेंद्र मेहरा, जिला बार एसोसिएशन हरिद्वार के अध्यक्ष नमित शर्मा आदि मौजूद रहे

आज बहादुराबाद में चार घंटे की बिजली कटौती होगी

हरिद्वार । ऊर्जा निगम आज बहादुराबाद क्षेत्र में चार घंटे की बिजली कटौती करेगा। मरम्मत काम के लिए दिन में तीन उपसंस्थानों से बिजली की सप्लाई बंद की जाएगी। इस कारण सोमवार को करीब 30 हजार की आबादी को बड़ी परेशानी होगी। कटौती के दौरान लोगों के जरूरी काम प्रभावित रहेंगे। साथ ही त्योहार सीजन में कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं, कटौती के दौरान लोगों को पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ेगा। सोमवार को ऊर्जा निगम उपकेंद्र ज्वालापुर के विद्युत उपसंस्थान सहदेवपुर, बहादुराबाद और ट्रांसपोर्ट नगर के फीडरों पर मरम्मत के काम करेगा। इस दौरान तीनों उपसंस्थानों के संबंधित फीडरों पर एएएससी कवर्ड कंडक्टर को बदलने और नए विद्युत पोल स्थापित करने का काम होगा। मरम्मत काम के लिए ऊर्जा निगम सुबह 10 बजे से क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बंद करेगा।

बालिका दिवस पर बेटियों ने संभाली प्रशासनिक कमान



हरिद्वार (संवाददाता) । जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की पहल पर अन्तराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत पांच बालिकाओं ने जिलाधिकारी के साथ सोमवार को एक दिन के लिए प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका निभाई और इस अनुभव के माध्यम से उन्होंने प्रशासनिक कार्यों, जिम्मेदारियों एवं जनसेवा के विभिन्न तरीकों को सीखा।

प्रशासनिक अधिकारी हेतु एक दिन के चयनित बालिकाओं ने सोमवार को जिला कार्यालय पहुँचकर जनसुनाई में पहुँचे फरियादियों की फरियाद सुनते हुए सरल समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण दिशा-

निर्देश सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को स्वयं दिये, जबकि कुछ जटिल समस्याओं पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से विचार-विमर्श करते हुए समस्या समाधान की दिशा में कार्य किया गया। जनसुनवाई की शुरुआत में जिलाधिकारी ने बेटियों को जनसुनवाई सहित जिला कार्यालय से संचालित होने वाले कार्यों से अवगत कराया।

इसके पश्चात एक दिन के लिए प्रशासनिक अधिकारी बनी बालिकाओं ने जिलाधिकारी के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जिलाधिकारी के साथ बैठकर समस्याएं सुनना एवं

उनका निस्तारण करना जिन्दगी के अदभुत लम्हों में से एक है। बालिकाओं ने कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आज के अनुभवों को साझा करेंगी और बालिका शिक्षा तथा लैंगिक समानता के लिए लोगों को प्रेरित करेंगी।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सरकारी विद्यालयों की बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जागरूक करने, बालिकाओं के शिक्षा और कैरियर के प्रति जागरूक करने, बालिकाओं के संवागीण विकास के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में इस कार्य को रिलैक्सो कम्पनी के सहयोग से संचालित किया गया।

इन्हें बनाया गया एक दिन के लिए प्रशासनिक अधिकारी शीतल पुत्री श्री तेलूराम, कक्षा 08, जेनरल शाहनवाज राजकीय उच्चतम विद्यालय ऐथल। तनीषा पुत्री श्री शमीम कक्षा 08, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुक्कनपुर ,लक्सर। ईशा गोयल पुत्री श्री प्रवेश गोयल कक्षा 11, नेशनल कन्या इंटर कॉलेज खानपुर। तमन्ना पुत्री श्री परविन्दर कुमार कक्षा 09 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर उर्द। अंशिका पुत्री श्री संदीप कुमार, कक्षा 12 अटल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज, मुण्डाखेडा कलां।

धामी सरकार - चली गरीब के द्वार



हरिद्वार (संवाददाता) । देशराज कर्णवाल उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति, उत्तराखंड सरकार राज्य मंत्री स्तर के नेतृत्व में दिनांक 13 अक्टूबर को "बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर" का ब्लॉक नारसन के 3 गांवों में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें शिविर के दौरान कुल 65 शिकायत इस प्रकार प्राप्त हुई है -

1. ठसका - 28 , 2. उदलहेड़ी - 12, 3. कुमराडा - 25

शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की जनसमस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान करना तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना था। शिविर में क्षेत्रीय नागरिकों ने सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में बढ़-चढ़कर भाग लिया और उत्साहपूर्वक अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कीं।

इनमें कई समस्याएं एक जैसी थी समस्याओं का समाधान शिविर स्थल पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया, जबकि कुछ जिला स्तर की समस्याएं थीं जिन्हें समाधान हेतु जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा।

इस अवसर पर कर्णवाल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए विभाग द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। शिविर में सभी संबंधित रेखीय विभागों के अधिकारीगण व कर्मचारीगण, ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्यगण एवं सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

ईईएसएल और भारतीय सेना के बीच एमओयू साइन

देहरादून । देश की अग्रणी परीक्षा तैयारी संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य सेना के सेवारत, सेवानिवृत्त, वीरता पुरस्कार विजेता, विकलांग कर्मियों तथा शहीद जवानों के परिवारों को शैक्षणिक सहयोग और कल्याणकारी लाभ प्रदान करना है।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कर्नल पी.आर. कथूरिया ने शिक्षा के माध्यम से सेना समुदाय को सशक्त बनाने में इस साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भारतीय सेना की ओर से सहायक एडजुटेंट जनरल, सेरेमोनियल एंड वेलफेयर 3 एवं 4, तथा ईईएसएल की ओर से दिल्ली-एनसीआर के मुख्य शैक्षणिक एवं

व्यवसाय प्रमुख डॉ. यशपाल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के तहत ईईएसएल देशभर में अपने सभी केंद्रों पर सेना से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष रियायतें और छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराएगा। इसके अंतर्गत वीरता पुरस्कार

विजेताओं और 20 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले कर्मियों के लिए 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस माफ। सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए 20 प्रतिशत ट्यूशन फीस में छूट, अन्य छात्रवृत्तियों की कटौती के बाद लागू होगी।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक अवनीश कुमार द्वारा भगवती प्रिंटर्स, इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार से छपवाकर ग्रा. बसवाखेड़ी पो. मंगलौर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।

सम्पादक: अवनीश कुमार, मो० 9410553400

ई-मेल: liveskgnews@gmail.com

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार न्यायालय में ही होगा)

सभी लेखों में सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं है।